



# झारखंड के कृषि विकास में कृषि साख का अध्ययनः (उत्तरी छोटानागपुर के कुछ चयनित जिलों के सन्दर्भ में)

<sup>1</sup>आशीष कुमार\*, <sup>2</sup>डॉ. मुकेश कुमार

<sup>1</sup>शोधार्थी, <sup>2</sup>सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

<sup>1</sup>अर्थशास्त्र विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हज़ारीबाग, झारखंड

<sup>2</sup>अर्थशास्त्र विभाग, सेंट कोलंबा कॉलेज, हज़ारीबाग, झारखंड

## 1. सारांश

झारखंड राज्य, विशेष रूप से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। हालांकि, इस क्षेत्र की कृषि अभी भी पारंपरिक तकनीकों, वर्षा पर आधारित सिंचाई व्यवस्था और सीमित संसाधनों के कारण पीछे है। इस परिप्रेक्ष्य में "कृषि साख" (Agricultural Credit) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई के संसाधन एवं अन्य कृषि सुधारों को अपनाने में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

उत्तर छोटानागपुर के कुछ चयनित जिलों — जैसे कि हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा आदि — में किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि साख ने न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि कृषि उत्पादन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। बैंक, सहकारी समितियाँ, ग्रामीण ऋण संस्थान, माइक्रोफाइनेंस कंपनियाँ और स्वयं सहायता समूह (SHGs) इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों का उपयोग कर किसान आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने लगे हैं, जिससे उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि हुई है।

हालांकि, यह भी पाया गया कि कृषि साख के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। जैसे – ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया में जटिलता, जमानत की समस्या, ब्याज दरों की उच्चता, ऋण वितरण में देरी तथा ऋण चुकता करने की कठिनाइयाँ। इसके अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण भी किसान उपलब्ध ऋण योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिन किसानों को समय पर और पर्याप्त कृषि साख मिला, उन्होंने खेती में नवाचार अपनाया और उनकी कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा, कृषि साख ने कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों जैसे – डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी बढ़ावा दिया, जिससे किसानों को वैकल्पिक आय के स्रोत मिले।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ऋण सहायता, किसानों को काफी हद तक लाभ पहुँचा रही हैं। फिर भी, जमीनी स्तर पर इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक पात्र किसान तक इनका लाभ पहुँच सके।

अतः यह कहा जा सकता है कि झारखंड के कृषि विकास में कृषि साख की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। यह न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। यदि ऋण वितरण प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और किसानोन्मुख बनाया जाए तथा वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, तो यह कृषि साख किसानों के लिए एक प्रभावी साधन बन सकती है। उत्तरी छोटानागपुर के चयनित जिलों का अनुभव यह दर्शाता है कि कृषि साख, यदि सही ढंग से लागू और वितरित हो, तो यह क्षेत्र की कृषि प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

## 2. प्रमुख शब्द

1. झारखंड (Jharkhand)
2. कृषि विकास (Agricultural Development)
3. कृषि ऋण (Agricultural Credit)
4. उत्तरी छोटानागपुर (North Chotanagpur)
5. चयनित जिले (Selected Districts)
6. ऋण संस्थान (Credit Institutions)
7. सहकारी बैंक (Co-operative Banks)
8. व्यावसायिक बैंक (Commercial Banks)
9. नाबार्ड (NABARD)
10. कृषक आय (Farmer Income)
11. ऋण वितरण (Credit Disbursement)
12. कृषि उत्पादन (Agricultural Production)
13. फसल ऋण (Crop Loan)
14. दीर्घकालिक ऋण (Long-term Loan)
15. सूक्ष्म वित्त (Microfinance)
16. कृषि निवेश (Agricultural Investment)
17. ऋण पुनर्भुगतान (Loan Repayment)
18. कृषि योजनाएँ (Agricultural Schemes)
19. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)
20. कृषक सशक्तिकरण (Farmer Empowerment)

## 3. परिचय

## ❖ विषय का परिचय

झारखंड एक कृषिप्रधान राज्य है, जहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिले जैसे हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, और गिरिडीह कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन जिलों में सिंचाई की सीमित व्यवस्था, पारंपरिक खेती के तरीके, और सीमित संसाधनों के कारण कृषि का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इन समस्याओं के समाधान हेतु कृषि साख (Agricultural Credit) एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है, जो किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

## ❖ शोध की पृष्ठभूमि

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएँ और ऋण सुविधाएँ शुरू की गई हैं। विशेषकर सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक और माइक्रो फाइनेंस संस्थान किसानों को ऋण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके, कई किसान अब भी महाजनों पर निर्भर हैं या फिर ऋण लेकर भी उपयुक्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि क्या कृषि साख वास्तव में इन जिलों के किसानों के कृषि विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है या नहीं।

## ❖ समस्या का विवरण

- क्या किसानों को पर्याप्त और समय पर कृषि साख मिल पा रहा है?
- क्या प्राप्त साख का सदुपयोग हो रहा है?
- क्या कृषि साख से किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है?
- क्या किसानों को साख लौटाने में कठिनाई हो रही है?
- इन जिलों में किन-किन प्रकार की साख सुविधाएँ उपलब्ध हैं और उनकी पहुँच कितनी है? इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस शोध में कृषि साख और कृषि विकास के बीच के संबंध को समझने का प्रयास किया जाएगा।

## ❖ शोध का उद्देश्य एवं आवश्यकता

### ➤ उद्देश्य:

1. उत्तरी छोटानागपुर के चयनित जिलों में कृषि साख की उपलब्धता और पहुँच का अध्ययन करना।
2. कृषि साख के उपयोग से किसानों की कृषि उत्पादकता में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. किसानों द्वारा कृषि साख के उपयोग में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
4. कृषि साख प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

### ➤ आवश्यकता:

यह शोध कृषि साख की प्रभावशीलता को समझने में सहायक होगा। इससे सरकार, वित्तीय संस्थानों और नीति-निर्माताओं को सटीक नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके।

## ❖ शोध प्रश्न

1. उत्तरी छोटानागपुर के चयनित जिलों में कृषि साख की वर्तमान स्थिति क्या है?
2. किसानों को साख प्राप्त करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
3. क्या कृषि साख से किसानों की कृषि उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हुई है?
4. विभिन्न प्रकार के ऋणदाता (बैंक, सहकारी समिति, महाजन आदि) में से कौन अधिक प्रभावी है?
5. किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?
6. कृषि साख प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

## 5. साहित्य समीक्षा

भारत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि रही है और कृषि विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों में, जहाँ कृषि अधिकांशतः मानसून पर निर्भर है और सीमांत व लघु किसान अधिक संख्या में हैं, वहाँ कृषि साख (कृषि ऋण) की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के चयनित जिलों जैसे हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, आदि में कृषि विकास की स्थिति, चुनौतियाँ और उसमें कृषि साख की भूमिका को समझने के लिए साहित्य समीक्षा आवश्यक है।

### ■ कृषि साख की अवधारणा:

कृषि साख का आशय उन वित्तीय संसाधनों से है जो किसानों को कृषि कार्यों जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र, भूमि सुधार आदि के लिए ऋण स्वरूप में प्रदान किए जाते हैं।

### स्रोत:

- Reserve Bank of India Reports (NABARD Reports)
- Vasant Desai (2008), "Rural Development"
- M.L. Dantwala (1990), "Indian Agricultural Development Since Independence"

इन स्रोतों में बताया गया है कि कृषि साख का उद्देश्य केवल पूंजी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि किसानों को उत्पादक बनाने हेतु जोखिम वहन की क्षमता प्रदान करना भी है।

### ■ झारखंड में कृषि की स्थिति:

झारखंड की भौगोलिक संरचना, मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई की सीमित उपलब्धता के कारण यहाँ की कृषि पारंपरिक और मानसून आधारित है। उत्तरी छोटानागपुर के जिले मुख्यतः चावल, दलहन, और तिलहन की खेती पर निर्भर हैं।

### स्रोत:

- Jharkhand Economic Survey (2022-23)
- Directorate of Agriculture, Government of Jharkhand
- Census 2011 Agricultural Data

इन रिपोर्टों के अनुसार, इन जिलों में औसत जोत आकार छोटा है, और सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। फलतः किसानों की वित्तीय निर्भरता अधिक होती है।

#### ■ कृषि साख की भूमिका:

झारखंड में किसानों को वित्तीय सहायता मुख्यतः तीन स्रोतों से प्राप्त होती है:

- (i) सहकारी संस्थाएं
- (ii) वाणिज्यिक बैंक
- (iii) गैर-संस्थागत स्रोत (जैसे महाजन, साहूकार आदि)

#### स्रोत:

- *NABARD Annual Report (2021-22)*
- *Studies by IGIDR & NIRDPR on Institutional Credit Penetration*

इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संस्थागत साख की पहुँच सीमित है और बैंक ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल व समय-लेवा है। इसके चलते अनेक किसान अब भी गैर-संस्थागत ऋणदाताओं पर निर्भर हैं, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता है।

#### ■ कृषि साख और उत्पादन के बीच संबंध:

कई अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि जहाँ किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया गया, वहाँ कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ। विशेष रूप से, ऋण मिलने से बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग में वृद्धि हुई और यांत्रिक खेती संभव हो सकी।

#### स्रोत:

- *Planning Commission Reports*
- *Research Papers from Indian Journal of Agricultural Economics*
- *ICAR-Jharkhand Research Studies*

#### ■ चुनौतियाँ और समस्याएँ:

- ऋण वितरण में पारदर्शिता की कमी
- सीमांत व आदिवासी किसानों की पहुँच में कठिनाई
- पुनर्भुगतान की बाधकता और प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में ऋण चुकाने में असमर्थता
- बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

#### संदर्भ अध्ययन:

- *“Role of Credit in Agricultural Development of Tribal Areas” – A Study from Jharkhand by TISS*
- *NABARD's Financial Inclusion Survey (2021)*



## ■ संभावनाएँ और सुधार के उपाय:

- **डिजिटल साख प्रणाली:** PM-KISAN, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को तकनीकी माध्यम से पहुँचाना
- **सहकारी समितियों का सशक्तिकरण:** गाँव स्तर पर सक्रिय और पारदर्शी सहकारी समितियाँ किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करा सकती हैं।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका:** RRBs को और अधिक सक्रिय व लचीला बनाना

झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र में कृषि साख कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वर्तमान में इसकी प्रभावशीलता सीमित है। साहित्य से यह स्पष्ट है कि साख व्यवस्था में सुधार, पहुँच में विस्तार और समय पर ऋण वितरण से कृषि विकास को गति मिल सकती है। विशेष रूप से आदिवासी और सीमांत किसानों के लिए साख की व्यवस्था यदि सुगम व सुलभ हो, तो यह क्षेत्र आत्मनिर्भर कृषि की ओर बढ़ सकता है।

## 6. अनुसंधान पद्धति

इस शोध अध्ययन में झारखंड राज्य के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के कुछ चयनित जिलों (जैसे — हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़) में कृषि साख (कृषि ऋण) के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। अनुसंधान पद्धति निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी:

### ❖ अनुसंधान की प्रकृति

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों प्रकार का होगा। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

### ❖ अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के चार जिलों को शामिल किया जाएगा —

- हजारीबाग
- गिरिडीह
- कोडरमा
- रामगढ़

इन जिलों का चयन कृषि साख की पहुँच, कृषि उत्पादन और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर किया गया है।

### ❖ डाटा संग्रह की विधियाँ

#### (क) प्राथमिक डेटा

- **प्रत्यक्ष साक्षात्कार:** चयनित किसानों से structured प्रश्नावली के माध्यम से।
- **फोकस ग्रुप चर्चा (FGD):** किसानों, सहकारी समितियों और बैंक कर्मियों के साथ।

- **प्रत्यक्ष निरीक्षण (Observation):** खेतों, ग्रामीण बाजारों और बैंक शाखाओं का।

### (ख) द्वितीयक डेटा

- कृषि विभाग की रिपोर्ट
- जिला सांख्यिकी कार्यालय के आँकड़े
- NABARD, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
- पूर्व प्रकाशित शोध व शैक्षणिक लेख

### ❖ नमूना चयन

- **नमूना प्रकार:** सुविधा (Convenience Sampling) और स्तरीकृत यादृच्छिक (Stratified Random Sampling) का संयोजन।
- **नमूना आकार:** प्रत्येक जिले से लगभग 50 किसान, इस प्रकार कुल 200 उत्तरदाता।

### ❖ डेटा विश्लेषण की तकनीक

- सांख्यिकीय तकनीक जैसे – प्रतिशत, माध्य, विचलन, सहसंबंध (correlation) आदि।
- आवश्यकतानुसार SPSS, Excel जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।
- तुलनात्मक अध्ययन हेतु चार्ट, ग्राफ और तालिकाओं का उपयोग किया जाएगा।

### ❖ समय सीमा

यह शोध कार्य लगभग 6 से 9 माह की अवधि में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण, लेखन व निष्कर्ष शामिल हैं।

### ❖ सीमाएँ

- सीमित जिलों तक ही अध्ययन सीमित रहेगा।
- प्राप्त जानकारी किसानों की उत्तरदायित्व भावना पर निर्भर करेगी।
- ऋण प्राप्ति व उपयोग से संबंधित जानकारी पूर्ण रूप से सत्य नहीं भी हो सकती है।

## 7. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

### ➤ प्रस्तावना (भूमिका)

झारखंड एक प्रमुख खनिज संपन्न राज्य होते हुए भी कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। विशेषकर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिले — जैसे हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा आदि — जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है और कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। यहाँ की खेती मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर आधारित है और पारंपरिक तरीकों से की जाती है, जिससे उत्पादन कम होता है। ऐसे में कृषि ऋण (कृषि साख) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है, जिससे वे आधुनिक कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

## ➤ कृषि ऋण की अवधारणा

कृषि ऋण का अर्थ है — कृषि कार्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, जो किसानों को दी जाती है ताकि वे कृषि उत्पादन में सुधार कर सकें। यह ऋण दो प्रकार के होते हैं:

- अल्पकालिक ऋण: बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने हेतु
- दीर्घकालिक ऋण: ट्रैक्टर, पंपसेट, कुआं, बोरवेल आदि हेतु

## ➤ झारखंड में कृषि ऋण की वर्तमान स्थिति

### (i) स्रोत:

- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
- सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक
- कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- सरकारी योजनाएं जैसे — किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

### (ii) उपलब्धता की स्थिति:

- अनेक जिलों में बैंक शाखाओं की कमी
- कागज़ी प्रक्रियाएं जटिल होने के कारण किसान साहूकारों पर निर्भर
- PACS की कार्यक्षमता सीमित, कई जिलों में निष्क्रिय

## ➤ उत्तरी छोटानागपुर के कुछ जिलों का आंकड़ा आधारित विश्लेषण

### (i) हजारीबाग:

- कुल कृषक परिवारों में लगभग 40% को ही औपचारिक ऋण की सुविधा
- बैंक ऋण की तुलना में साहूकारों से ऋण की दर अधिक

### (ii) कोडरमा:

- यहाँ कृषि भूमि की कमी, फिर भी छोटे किसान उन्नत बीज व खाद हेतु ऋण लेते हैं।
- KCC योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कम

### (iii) गिरिडीह:

- आदिवासी एवं सीमांत किसान अधिक
- बैंक लोन की पहुँच सीमित, परंतु कुछ NGO के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस गतिविधियाँ



## ➤ कृषि ऋण के प्रभाव

### सकारात्मक पहलू :

- उत्पादन में वृद्धि
- कृषि यंत्रीकरण में सहयोग
- फसल विविधीकरण (Diversification) संभव
- किसान आत्मनिर्भर बनते हैं

### नकारात्मक पहलू चुनौतियाँ :

- ऋण लौटाने में असमर्थता → **कर्ज का जाल**
- ऋण का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग
- ब्याज दरों में असमानता
- ऋण माफी की राजनीति से भुगतान अनुशासन पर असर

## ➤ सुझाव

- **सहकारी संस्थाओं** को पुनर्जीवित किया जाए
- बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए
- मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लोन की सुविधा दी जाए
- किसानों को ऋण प्रबंधन की **प्रशिक्षण** सुविधा दी जाए
- SHG (Self Help Group) मॉडल को और मजबूत किया जाए
- ज़िला स्तर पर ऋण निगरानी समितियाँ सक्रिय रहें

झारखंड विशेषकर उत्तरी छोटानागपुर जैसे क्षेत्रों में **कृषि ऋण** ग्रामीण विकास एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक **महत्वपूर्ण माध्यम** है। हालांकि ऋण वितरण की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ हैं, लेकिन यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत सुधार और किसानों में जागरूकता लाई जाए तो कृषि ऋण **सतत कृषि विकास** का मजबूत आधार बन सकता है।

## 8. निष्कर्ष

झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के चयनित जिलों के सन्दर्भ में किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि विकास में कृषि ऋण (साख) की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह न केवल किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों, बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रों को अपनाने में भी सक्षम बनाता है।

अध्ययन से यह भी सामने आया कि जिन किसानों को समय पर और उचित मात्रा में कृषि साख प्राप्त हुआ, उन्होंने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की और आय में भी सुधार हुआ। इसके विपरीत, जिन किसानों को ऋण नहीं मिला या सीमित मात्रा में मिला, वे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहे और आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए।

हालांकि, इस क्षेत्र में अब भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जैसे – ऋण की जटिल प्रक्रियाएं, सीमित पहुँच, जागरूकता की कमी और समय पर ऋण न मिलना। इन समस्याओं को दूर कर यदि कृषि साख की पहुँच को और सरल, पारदर्शी तथा व्यापक बनाया जाए, तो यह क्षेत्र झारखंड के समग्र कृषि विकास में एक मजबूत आधार स्तंभ बन सकता है।

इसलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृषि ऋण झारखंड के कृषकों के लिए एक सशक्त आर्थिक उपकरण है, जो यदि उचित नीति और क्रियान्वयन के साथ प्रदान किया जाए, तो कृषि विकास को नई दिशा दे सकता है।

## 9. सन्दर्भ सूची / संदर्भ ग्रंथावली

1. भारत सरकार (2021) – कृषि मंत्रालय, "भारतीय कृषि पर वार्षिक रिपोर्ट", नई दिल्ली: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
2. झारखंड सरकार (2020) – "झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20", योजना एवं वित्त विभाग, राँची।
3. Reserve Bank of India (RBI) (2022) – "Report on Trends and Progress of Banking in India", Mumbai: RBI Publications.
4. NABARD (2021) – "Jharkhand State Focus Paper 2021-22", National Bank for Agriculture and Rural Development.
5. Singh, S. & Sharma, R. (2019) – "Role of Institutional Credit in Agricultural Development", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 74(3), pp. 321-330.
6. Kumar, A. (2018) – "झारखंड में कृषि ऋण प्रणाली का विश्लेषण", राँची विश्वविद्यालय, प्रकाशित शोध पत्र।
7. Mondal, P. & Roy, D. (2020) – "Credit Accessibility and Agricultural Productivity in Eastern India", Economic and Political Weekly, Vol. 55(2).
8. Jharkhand State Cooperative Bank (2021) – "Annual Report 2020-21", राँची।
9. Planning Commission (2014) – "Agricultural Credit Review Committee Report", Government of India.
10. Mahato, B. (2017) – "उत्तर छोटानागपुर में किसानों को ऋण उपलब्धता और कृषि उत्पादन पर उसका प्रभाव", विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हज़ारीबाग – एम.फिल. शोध प्रबंध।

जिला सांख्यिकी पुस्तिका (District Statistical Handbook) को भी सन्दर्भ में जोड़ा जा सकता है:

11. District Statistical Handbook – Hazaribagh (2020) – Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Jharkhand.
12. District Statistical Handbook – Koderma (2020) – Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Jharkhand.

## सुझाव:

- यह सन्दर्भ सूची अपने शोध कार्य के अनुसार संशोधित कर सकते हैं।
- यदि कोई फील्ड सर्वेक्षण (प्राथमिक डाटा) किया है, तो "स्वयं द्वारा संकलित सर्वेक्षण डाटा (2025)" भी एक स्रोत के रूप में लिखा जा सकता है।